खेलों को बढ़ावा देने सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स और 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का किया शुभारंभ

भोपाल, 26 नवंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के चहुँमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है. खेल विभाग प्रदेश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रहा है.

भारत की प्राचीन संस्कृति में खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासन, संतुलन और मानसिक दृढ़ता का माध्यम माने गए हैं. पुराने समय में नौकायन, तैराकी और जल प्रशिक्षण को सामरिक और शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था. वही परंपरा आज वॉटर स्पोर्ट्स के रूप में हमारे सामने है. इसमें तकनीक, सहन शक्ति और फोकस का वास्तविक परीक्षण होता है. राज्य सरकार के लिए रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी करना गर्व और आनंद का विषय है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को भोपाल के बड़े तालाब स्थित बोट क्लब पर 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स और 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

> खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह 4 दिवसीय रोइंग चैंपियनशिप, वॉटर स्पोर्ट्स के कुंभ के रूप में स्थापित होगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार खेल-खिलाड़ी और खेल मैदान को प्रोत्साहित करने के लिए संपूर्ण प्रदेश में प्रयास कर रही है. खेलों और खिलाड़ियों को आवश्यक प्रशिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉलेज एक्सचेंज के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कोच तथा खिलाड़ी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चैंपियनशिप के शुभारंभ की घोषणा की. उन्होंने चैंपियनशिप में शामिल 23 राज्यों के लगभग 500 खिलाड़ियों द्वारा देशभक्ति गीतों की धुनों पर प्रस्तुत मार्च पास्ट का अवलोकन किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव के आयोजन स्थल पहुंचने पर उन्हें कैप लगाकर स्वागत किया गया. इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग, भोपाल महापौर मालती राय सहित अधिकारी एवं खेल प्रेमी विशेष रूप से उपस्थित थे.

सीएम आज श्योपुर में किसानों को फसल बीमा राशि वितरित करेंगे

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 नवंबर को श्योपुर जिले के बड़ौदा में आयोजित कार्यक्रम में श्योपुर सहित 6 जिलो के किसानों को फसल क्षति की राहत राशि का वितरण करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव 3 लाख 5 हजार 410 प्रभावित किसानों के बैंक खातों में 238 करोड़ 78 लाख रूपये की राशि अंतरित करेंगे. श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार, खण्डवा जिलों की 23 तहसीलों के 2 हजार 148 ग्रामों के किसानों को अतिवृष्टि, बाढ और पीला मौजेक कीट व्याधि से हुई फसल क्षति की राहत राशि अंतरित की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव इसी दिन मुरैना जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 162 करोड़ 55 लाख रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन करेंगे.

भोपाल, 26 नवंबर. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से बुधवार की शाम मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भेंट की.

परिषद की बैठक में हेलमेट पहनकर आये भाजपा पार्षद

सीधी. नगर पालिका परिषद की बैठक में भाजपा पार्षद बुधवार को हेलमेट पहनकर आये. नगरपालिका परिषद सीधी की पिछली बैठक में कांग्रेसी पार्षदों के बीच हुये पानी बाटल युद्ध का भाजपा पार्षदों का विरोध का अनोखा प्रदर्शन रहा. नपा में 14 नवम्बर को हुई बैठक में पार्षदों के बीच हुई नूराकुश्ती का असर बुधवार को भी आयोजित बैठक के दौरान देखने को मिला है. परिषद की बैठक में पहुंचे भाजपा पार्षदों ने हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट के सवाल पर सभी ने गत बैठक में हुई नूराकुश्ती का जिक्र करते हुए कहा कि अब सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा.

अनुपम राजन को जनसंपर्क का प्रभार

गणेश कुमार जायसवाल अपर संचालक जनसंपर्क संचालनालय पदस्थ

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 26 नवंबर. राज्य सरकार ने अनुपम राजन अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग तथा एसीएस उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, एसीएस संसदीय कार्य विभाग अतिरिक्त प्रभार को अपने मौजूदा दायित्वों के साथ अपर मुख्य सचिव जनसंपर्क विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा है.

यहां बता दें कि वर्ष 1993 बैच के आईएएस अनुपम राजन वर्ष 2016-17 की अवधि में जनसंपर्क आयुक्त भी रह चुके हैं. विभाग में अब तक प्रमुख सचिव

या अपर मुख्य सचिव पदस्थ नहीं होने के कारण ऐसे विषय जिन पर शासन स्तर पर निर्णय होने होते हैं, वे लगातार लंबित हो रहे थे.

ऐसे में अब राज्य सरकार ने राजन को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं. राजन एक दिसंबर 2024 से अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

> इधर एक अन्य आदेश में गणेश कुमार जायसवाल उपायुक्त राजस्व नर्मदापुरम संभाग को अपर संचालक जनसंपर्क संचालनालय भोपाल के पद पर पदस्थ किया गया है. जायसवाल राज्य प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2012 के अधिकारी हैं. ये पहली बार है कि जनसंपर्क संचालनालय में अपर संचालक के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पदस्थ किया गया है.

संविधान की प्रतियां सौंपते पुलिस ने कांग्रेसियों को घेरा

जबलपुर. संविधान दिवस के मौके पर बुधवार को रानीताल चौक में कांग्रेसियों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया. जिसके बाद कांग्रेसियों का स्पष्ट कहना था कि साहब हम लोग कोई अपराधी थोड़ी न हैं हम लोग तो गांधीवादी सोच के नेता हैं, जो संविधान दिवस पर संविधान की प्रतियां भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर और पुलिस प्रशासन को देने आए थे. जानकारी के अनुसार कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का समूह संविधान की प्रतियां, ग्रंथ को देने रानीताल चौराहे में एकत्रित हुआ था लेकिन इस दौरान वहां भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर नहीं आए.

स्कूल की सामग्री खरीदी में नियमों की अनदेखी

रुनाहा हायर सेकंडरी स्कूल का मामला

बैरसिया, 26 नवंबर. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुनाहा में डेढ़-दो साल से गंभीर अनियमितताएं की जा रहीं हैं. स्कूल की सामग्री खरीदी में शासन के नियमों की अनदेखी की जा रही है. इस स्कूल में संकुल प्राचार्य प्रकाश विजयवर्गीय पदस्थ हैं.

स्कूल के सूत्रों की बात पर भरोसा किया जाए तो जहां की स्कूल व्यवस्था के लिए वितरण किए प्रभारों में स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों की खुली अनदेखी की गई है. सूत्र बताते हैं कि प्राचार्य ने रमसा मद का प्रभार अपने पास रखा है और वे इस मद की समस्त राशियों का खर्च मनमर्जी से कर रहे हैं. इतना ही नहीं प्राचार्य द्वारा विद्यालय के अन्य मदों की राशियों को नियम विरुद्ध रमसा मद में ट्रांसफर कर खर्च की गई है. इसकी पुष्टि रिकॉर्ड मिलान से की जा सकती है. इधर विद्यालय में शाला विकास, लाइब्रेरी, लैब, स्थापना जैसे प्रभार वरिष्ठों को छोड़ कनिष्ठ शिक्षकों को दिए गए हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल में क्रय-विक्रय समिति तो गठित की गई, लेकिन समिति सदस्यों को क्रय-विक्रय की जानकारी नहीं दी जाती है. सूत्रों ने रमसा मद से पाठ्य पुस्तक क्रय और मरम्मत कार्य एवं पुराने कुर्सी - टेबलों और अलमारियों की रिपेयरिंग और पुताई कराकर चमकाकर खरीदी के बिल वाउचर और कोटेशन लगाने का संदेह जताया है. सूत्रों का कहना है कि खरीदी गई सामग्री का रिकॉर्ड से मिलान कर भौतिक सत्यापन होना स्कूल हित में जरूरी है.

> **इनका कहना है.**
> इस प्रकार की शिकायत संज्ञान में नही है. स्कूल को प्राप्त राशियों की जांच कराएंगे, इसमें अनियमितता मिली तो कार्यवाही करेंगे.
> **एनपी अहिरवार,** जिला शिक्षा अधिकारी

नसबंदी के लिए पुरुषों को किया जागरूक

बैरसिया में जनजागरण प्रचार-प्रसार रैली निकाली

बैरसिया, 26 नवंबर. राष्ट्रीय परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रम पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मंगलवार से शुरू हो गया है. जो 4 दिसंबर तक चलेगा. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष शर्मा के निर्देशन में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. पुष्पा गुरु ने पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के सफल क्रियान्वयन के लिए नगर में जनजागरण प्रचार - प्रसार रैली को अस्पताल से हरी झंडी दिखा कर रवाना की.

बीएमओ डॉ. गुरु ने बताया कि पुरुष नसबंदी (एनएसवी) पखवाड़ा अंतर्गत शासकीय एव चिन्हित निजी अस्पतालो में

नसबंदी की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध है. जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा पुरुष नसबंदी की जाएगी. पखवाड़े में नसबंदी कराने वाले पुरुष को तीन हजार एवं प्रेरक को चार सौ रुपए प्रदान किए जाएंगे. पुरुष नसबंदी पखवाड़े में अस्पताल की टीम गांव गांव जाकर पुरुषों को एनएसवी के लिए प्रेरित कर नसबंदी के ग्राफ को बढ़ायेगी. प्रचार-प्रसार रैली में डॉ पुष्पा गुरु मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी, शेखर सिंह, अशोक सिरोलिया, अर्जुन ठाकुर, नीलेश पांडे, मिथलेश, आईशा खान, अफसाना बी, रेणुका, रिहाना, दीपक नामदेव, कमलेश तोमर, अरुण कुमार भाऊ आदि शामिल थे.

आज हो सकता है बैकलॉग शिक्षकों की भर्ती का फैसला

जबलपुर. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बैकलॉग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. विगत वर्ष भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई तरह की शिकायतें विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंची थीं. जिसमें कुछ अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एमपी हाईकोर्ट पहुंचे थे. हालांकि एमपी हाईकोर्ट ने लिफाफा लौटाते हुए उसे खोलने से इनकार कर दिया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस सीलबंद लिफाफे को रादुविवि की होने वाली कार्यपरिषद बैठक में प्रस्तुत किया गया है, संभावना है कि आज बैठक में सीलबंद लिफाफा खोला जाएगा.

मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी को नेशनल अवार्ड

- **देहरादून में दिसंबर में प्रदान किया जाएगा अवॉर्ड**
- **प्रबंध संचालक सिंघल ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दी बधाई**

भोपाल 26 नवंबर. ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों को पीआरएसआई नेशनल अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है. यह अवार्ड आगामी 13 से 15 दिसंबर 2025 तक देहरादून में आयोजित 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदान किया जाएगा. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कंपनी को मिले इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है.

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बिजली क्षेत्र में किये जा रहे उल्लेखनीय विकास कार्यों के लिए पीआरएसआई नेशनल अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्थापित किये जा रहे स्मार्ट मीटर, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपाय एप और अत्याधुनिक केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर 1912, एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला जैसी सेवाओं के साथ उपभोक्ता संतुष्टि के साथ विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. गौरतलब है कि पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया जनसम्पर्क एवं संचार के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों में कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स की एक राष्ट्रीय स्तर की 70 वर्ष पुरानी संस्था है.

> इस संस्था के पूरे देश में अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, भुबनेश्वर, चंडीगढ़, चैन्नई, दिल्ली, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, सिंगरौली, शिमला, तिरुपति, वाराणसी, विशाखापत्तनम, जम्मू, अमरावती और वर्धा सहित 23 चैप्टर कार्यरत हैं.

100% मैपिंग करने पर बीएलओ को दिए प्रशस्ति पत्र

उदयपुरा. रायसेन जिले के विधानसभा क्षेत्र 140 उदयपुरा के मतदान केंद्र क्रमांक 170- कुचवाड़ा, 179- सिलारी खुर्द, 182- आंवरिया, 220- कल्हेडी कला, 242- ककरुआ, 253- कैल्कच्छ के बीएलओ के द्वारा एसआईआर कार्य अंतर्गत मतदाताओं की 100 प्रतिशत मैपिंग करने पर तहसील उदयपुरा के तहसीलदार दिनेश बरगले, एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास खुशबू अग्रवाल एवं निर्वाचन सुपरवाइजर राजेंद्र गोदानी द्वारा बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गए।

एसआईआर को लेकर मतदाता दर्ज करा सकते हैं शिकायत

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 26 नवंबर. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश कार्यालय ने जानकारी दी है कि मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर से जुड़ी अपनी सभी शिकायतें सरल, पारदर्शी और प्रभावी माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं, जिनके समयबद्ध समाधान की व्यवस्था राज्यभर में सुनिश्चित की गई है. फॉर्म वितरण, डाटा सत्यापन, बीएलओ संपर्क, मतदाता सूची त्रुटियों और अन्य निर्वाचन कार्यों से संबंधित शिकायतों के लिए प्रदेश में व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली संचालित है.

मतदाता अपनी शिकायतें राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं, जो एक टोल-फ्री सेवा है. शिकायत दर्ज होते ही कॉल करने वाले को एक टोकन आईडी प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से वह बाद में अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकता है. ऑनलाइन सुविधा के रूप में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी में भी शिकायत पंजीकृत की जा सकती है, उसका निवारण तय समय-सीमा में किया जाता है.

कमजोर वर्गों को दें योजनाओं का लाभ

समीक्षा बैठक में मंत्री कुशवाह ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 26 नवंबर. सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि विभाग का मूल उद्देश्य समाज के असहाय और कमजोर वर्गों तक संवेदनशीलता के साथ योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.

उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग केवल प्रशासनिक कार्यवाही का ढांचा नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना से संचालित एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसका केन्द्र बिंदु जरूरतमंद नागरिकों का सशक्तिकरण है. मंत्री कुशवाह ने यह बात विभागों के 2 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा बैठक में कही.

मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, निराश्रितजन, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं सहित सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर सहायता मिलना सरकार की प्राथमिकता है.

> उन्होंने निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए और फील्ड स्तर पर हितग्राहियों से सीधा संवाद बढ़ाया जाए. कुशवाह ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का त्वरित निराकरण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए विभागीय सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि समाज के सबसे कमजोर लोगों के साथ व्यवहार में संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण सर्वोपरि होना चाहिए.

संविधान दिवस पर ली शपथ

भोपाल. पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने संविधान दिवस के अवसर पर कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई. भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठन और मौलिक कर्तव्यों से कमिश्नर ने सभी को अवगत कराया. इसके साथ ही संविधान में निहित मूल्यों और आदर्शों की जानकारी सभी के साथ साझा की गई.

शहर में अवैध पार्किंग सिरदर्द बनी है.

भोपाल. शहर में अवैध पार्किंग की समस्या ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के लिए सिरदर्द बनी है. कलेक्ट्रेट के सामने मुख्य सड़क के किनारे ही चार पहिया वाहन चालक हर रोज अपने वाहनों को पार्क कर रहे हैं, जिससे राहगीरों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

तैयारी | मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में दिये निर्देश

भोपाल सहित 7 शहरों में हवा बेहतर बनाने कार्ययोजना

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 26 नवंबर. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के प्रमुख 7 नगरों में उच्च वायु गुणवत्ता स्तर बनाए रखने के लिए मौजूद समय के साथ ही दीर्घकालीन कार्ययोजना 30 नवम्बर तक प्रस्तुत करने के निर्देश पर्यावरण संरक्षण और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं.

मंत्रालय में बुधवार को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में वन और पर्यावरण, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, गृह, औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, परिवहन आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. वी.सी के माध्यम से भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर तथा देवास के कलेक्टर, एस पी, और नगर निगम के आयुक्त भी शामिल हुए. मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय क्लीन एयर प्रोग्राम के मापदंडो के अनुरूप दिल्ली जैसे महानगरों में प्रदूषण के स्तर को कम कर वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को केंद्र में रखकर प्रमुख विभागों का एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाएं और लघु तथा दीर्घ कालीन कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए. मुख्य सचिव ने पराली जलाने की घटनाओं को भविष्य में भी रोकने के प्लान के अलावा वाहनों, निर्माण कार्यों और कचरे आदि में आग लगाने जैसी प्रवृत्तियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पृथक-पृथक एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि सड़कों की धूल रोकने के लिए उनकी मरम्मत आदि करने के साथ गुणवत्ता बनाए रखने पर ध्यान दें. गुणवत्ता विहीन सड़कों के निर्माण के लिए अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्यवाही की जाए.

निर्माण कार्यों के प्रदूषण को रोकें

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नागरिकों के निवास आदि के निर्माण के साथ ही अन्य बड़े निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नेट लगाने के साथ ही जल के नियमित छिड़काव आदि को सुनिश्चित करें. निर्माण के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए अलग-अलग प्रभावी मापदंड-कार्ययोजना में शामिल किये जाएं.

वायु गुणवत्ता मानक 100 के नीचे लाएं

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर ठीक नहीं है, उनका पूरा ध्यान वायु गुणवत्ता को औसत मानक 100 से नीचे होना चाहिए. नगर निगम ध्यान दें कि कचरा जलाने पर शत-प्रतिशत रोक हो, निर्माण कार्यों से धूल न उठे और सड़कों का सुधार और पुन:निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ करें. उन्होंने अलाव-तंदूर जैसे कारकों को इलेक्ट्रिक किया जाए. धूल वाले स्थानों पर नियमित रूप से जल के छिड़काव करने के साथ ही पी.यू.सी प्राप्त वाहनों का संचालन के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाए.